दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शुक्रवार 24 जुलाई 2020 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-02, अंक- 295

आईसीएमआर ने पहली स्वदेशी एंटीजन किट को दी मंजूरी

450 रुपये में होगी जांच, 30 मिनट में आएगा परिणाम

नईदिल्ली (आरएनएस)। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने कोरोनावायरस का पता लगाने के लिए बुधवार को मायलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस द्वारा बनाई दूसरे रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। यह पहली भारतीय किट है जिसे मान्यता प्राप्त हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में बनाई गई पहली रैपिड एंटीजन किट का नाम पैथोकैच कोविड-19 रखा गया है। यह तुरंत ऑर्डर किया जा सकेगा और इसकी कीमत 450 रुपये है। मायलैब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पोलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट किट पहली भारतीय किट थी जिसे आईसीएमआर से मंजूरी मिली थी।

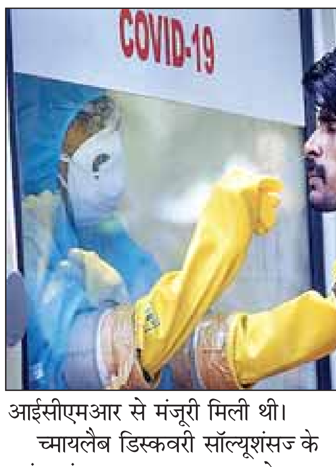

च्मायलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंसज के प्रबंध संचालक हसमुख रावल ने कहा कि मायलैब की टीम इस महामारी से लड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आरटी-पीसीआर टेस्ट को सस्ती दरों पर मुहैया कराकर हमने विदेशी किटों पर से निर्भरता कम की और अब हमने कोविड-19 टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए कॉम्पैक्ट एक्सएल को लॉन्च किया है।

उन्होंने कहा कि अब एंटीजन टेस्टिंग किट के लिए मंजूरी मिलने के बाद, हम कोविड-19 के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर कर सकेंगे। साथ ही इस महामारी से लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मायलैब का चरियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पोलीमरेज चेन रिएक्शनज (आरआरटी-पीसीआर) टेस्ट किट भी पहली स्वदेशी जांच किट थी, जिसे भारत में उपयोग के लिए आईसीएमआर की मंजूरी मिली थी।

एंटीजन-आधारित टेस्टिंग का उपयोग आरआरटी-पीसीआर के साथ-साथ देश के समग्र टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने और रोगियों का इलाज करने के लिए किया जा रहा है। रैपिड एंटीजन टेस्ट आरआरटी-पीसीआर की तुलना में कम वक्त लेता है, क्योंकि आरआरटी-पीसीआर टेस्टिंग के लिए लगभग पांच घंटे का समय लगता है, जबकि इसमें सिर्फ 30 मिनट लगते हैं। वहीं, एंटीजन टेस्ट के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि आरआरटी-पीसीआर टेस्टिंग के लिए प्रयोगशाला की जरूरत होती है।

महत्वपूर्ण एवं खास

ट्रम्प देश का "पहला" नस्लीय राष्ट्रपतिःबाइडेन

वाशिंगटन। अमेरिका में नवम्बर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के संभावित उम्मीदवार जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को देश का ''पहला'' नस्लीय राष्ट्रपति बताया है।सेवा कर्मचारी अंतरराष्ट्रीय संघ द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम में उन्होंने यह बयान दिया।कार्यक्रम के दौरान जब एक व्यक्ति ने कोरोना वायरस को लेकर नस्लवाद और राष्ट्रपति के इसे ''चीनी वायरस'' बताने के संदर्भ में शिकायत की तो बाइडेन ने ट्रम्प की आलोचना की और ''नस्लवाद फैलाने'' के लिए उन पर निशाना साधा।पूर्व उप राष्ट्रपति ने कहा, '' वह जिस तरह से लोगों से उनके रंग, उनके राष्ट्र को देखकर व्यवहार करते हैं, यह दुखद है।''उन्होंने कहा, '' किसी भी राष्ट्रपति ने कभी ऐसा नहीं किया। कभी नहीं। किसी रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने भी ऐसा नहीं किया।

कोरोना के मामले बढ़ने के मद्देनजर ट्रंप ने की मदद की घोषणा

वाशिंगटन। कोविड-19 के मामले बढ़ने से नर्सिंग होम में मरीजों की मौत की आशंकाओं के मद्देनजर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महामारी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य केंद्रों को पांच अरब डॉलर की मदद देने की घोषणा की है। यह कदम राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के संभावित उम्मीदवार जो बाइडेन द्वारा पारिवारिक देखभाल योजना की घोषणा के बाद उठाया गया है। बाइडेन की योजना का उद्देश्य बुजुर्गों के लिए संस्थागत देखभाल के विकल्पों का विस्तार करना और सब्सिडी देना है। ट्रंप और बाइडेन आगामी राष्ट्रपति चुनावों में देश के वरिष्ठ नागरिकों का समर्थन और वोट पाने का प्रयास कर रहे हैं।

ह्यूस्टन में चीन के वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश, तनाव बढ़ा

वाशिंगटन। अमेरिका ने चीन को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है जिससे दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव बढ़ गया है। देश में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन के खिलाफ कड़े कदम उठाने के सिलसिले में यह नया कदम है। चीन ने बुधवार को इस आदेश की निंदा करते हुए इसे ''अपमानजनक'' बताया और कहा कि अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका में चीन के छह वाणिज्य दूतावासों में से एक को बंद करने से तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच न केवल कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर बल्कि व्यापार, मानवाधिकारों, हांगकांग और दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे को लेकर भी तनाव चल रहा है।चीनी अधिकारियों, छात्रों और शोधकर्ताओं के खिलाफ ट्रंप प्रशासन के पहले उठाए गए कदमों में यात्रा प्रतिबंध, पंजीकरण आवश्यकताएं और अमेरिका में चीनी नागरिकों की मौजूदगी कम करने की मंशा वाले अन्य कदम भी शामिल हैं।

ताइवान से जंग की तैयारी में जुटा चीन

ताइपे। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नौसेना के युद्धाभ्यास से बेपरवाह चीन ताइवान पर कब्जे की तैयारी में जुट गया है। यही नहीं चीन अब हर लगभग हर दिन ताइवान की सीमा में फाइटर जेट भेज रहा है। यह कहना है ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू का। वू ने कहा कि चीन बलपूर्वक ताइवान पर कब्जे की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से चीन न केवल ताइवान पर हमले का अभ्यास कर रहा है, बल्कि हर दिन अपने फाइटर जेट को हमारे एयर स्पेस में भेज रहा है। यह हमारे लिए चिंता का सबब बन गया है। ताइवान के विदेश मंत्री ने कहा कि चीन धीरे-धीरे अपनी सैन्य तैयारी को खासतौर पर हमारे देश के हवाई इलाके और समुद्र में बढ़ा रहा है। चीन सैन्य तैयारी के जरिए ताइवान के मुद्दे को सुलझाना चाहता है। वून ने कहा, खतरा अब बढ़ता ही जा रहा है। उधर, चीन का दावा है कि इस तरह के युद्धाभ्यास का मकसद यह दर्शाना है कि हमारा देश अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। चीन का कहना है कि ताइवान उसका हिस्सा है और उस नियंत्रण के लिए सैन्य हमले की धमकी भी दी है।

हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार

राजस्थान विधानसभा स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट का झटका

नईदिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने संबंधी राज्य विधानसभा अध्यक्ष का अनुरोध गुरुवार को ठुकरा दिया। न्यायालय ने हालांकि, यह स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट एवं उनके खेमे के 18 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में उच्च न्यायालय का कोई भी फैसला शीर्ष अदालत के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल तथा पायलट खेमे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह इस मामले में सोमवार को विस्तृत सुनवाई करेगी। इस बीच उच्च न्यायालय के मंगलवार के आदेश पर रोक नहीं लगेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस बाबत सुनवाई करेगी कि क्या उच्च न्यायालय सदन के अध्यक्ष के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर सकता है या नहीं? खंडपीठ अध्यक्ष के अधिकार बनाम अदालत के क्षेत्राधिकार जैसे महत्वपूर्ण सवाल पर विचार करेगी। न्यायालय ने हालांकि यह भी स्पष्ट कर दिया कि उच्च न्यायालय का 24 जुलाई का कोई भी फैसला इस मामले में शीर्ष अदालत के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। राजस्थान के स्पीकर की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि क्या चुने गए प्रतिनिधि अपनी असहमति नहीं जता सकते? अगर असहमति को दबाया जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा।

अब फ्लोर टेस्ट का सहारा ले सकती है गहलोत सरकार

नई दिल्ली(आरएनएस)। राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट की सियासी जंग को भाजपा लंबा खींचना चाहती है। अगर शुक्रवार को हाईकोर्ट से सचिन पायलट सहित अन्य बागियों को राहत मिली तो पायलट कांग्रेस में रह कर गहलोत सरकार का दर्द बढ़ाते रहेंगे। भाजपा खेमे का मानना है कि अदालती लड़ाई में हार के बाद गहलोत सरकार जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट का सहारा ले सकती है।

बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई इस मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने जिस प्रकार की कई टिप्पणियां की है, उससे भाजपा की उम्मीदें बंधी हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति की आवाज तो नहीं दबाया जा सकता। इस दौरान शीर्ष अदालत ने यह भी पूछा कि महज पार्टी बैठक में नहीं आने केआधार पर ही किसी विधायक को अयोग्य ठहराया जा सकता है? हालांकि पार्टी की निगाहें फिलहाल शुक्रवार को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर है।

स्कूल फीस संबंधी याचिका पर सुको का निर्देश

नई दिल्ली(आरएनएस)। कोरोना संकट के कारण देश में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान स्कूलों से फीस लेने से मना करने संबंधी मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों की ओर से बच्चों से सिर्फ ट्यूशन फीस लेने संबंधी आदेश पारित करने पर संदेह व्यक्त किया. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर कहा कि पूरे देश के लिए एक समान आदेश पारित नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में हाईकोर्ट जाने को कहा है।

अब सेना में महिलाओं को मिलेगा स्थायी कमीशन

सरकार ने जारी किया स्वीकृति पत्र

नई दिल्ली(आरएनएस)। भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने को लेकर सरकार ने गुरुवार को औपचारिक स्वीकृति पत्र जारी कर दिया है। अब इससे सेना में बड़ी भूमिका निभाने के लिए महिला अधिकारियों के लिए सशक्त मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। यह जानकारी भारतीय सेना के प्रवक्ता ने दी। यह आदेश भारतीय सेना की सभी दस स्ट्रीम में शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) की महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए निर्दिष्ट करता है। जैसे ही सभी प्रभावी एसएससी महिला अधिकारी अपने विकल्प का प्रयोग करती हैं और अपेक्षित दस्तावेज पूरा कर लेती हैं, उनका चयन बोर्ड निर्धारित किया जाएगा।

गौरतलब है कि सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार युद्ध क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी इलाकों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमान देने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने कहा था कि सामाजिक और मानसिक कारण बताकर महिलाओं को इस अवसर से वंचित करना न केवल भेदभावपूर्ण है, बल्कि अस्वीकार्य भी है।

रेलवे ने 63 लाख प्रवासियों की कराई घर वापसी

एक मई से नौ जुलाई तक चलाई गई 4615 श्रमिक विशेष ट्रेने

नई दिल्ली (आरएनएस)। रेलवे ने बृहस्तिवार को कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को उनके अपने राज्य पहुंचाने के लिये श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की सभी मौजूदा मांग उसने पूरी कर दी है। इसके तहत अंतिम ट्रेन सेवा नौ जुलाई को प्रदान की गई।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी. के. यादव ने गुरुवार को ऑनलाइन एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एक मई से कुल 4,615 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। इनके जरिये 63 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान घर पहुंचाया गया।

रेलवे ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान फंसे हजारों श्रमिकों के अपने-अपने घरों के लिये पैदल ही निकल पड़ने के बाद उन्हें उनके मूल निवास वाले राज्य में पहुंचाने के लिये एक मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। रेल मंत्रालय ने कहा है कि उसने प्रवासी श्रमिकों के लिये टिकटों की कीमत में रियायत दी। केंद्र टिकट की कीमत का 85 प्रतिशत हिस्सा देने को राजी हुआ, जबकि राज्यों से 15 प्रतिशत हिस्से का भुगतान करने को कहा गया।

यादव ने कहा कि अंतिम श्रमिक स्पेशल ट्रेन नौ जुलाई को परिचालित की गई थी और इसके साथ ही यह मान लिया गया कि हमने इन ट्रेनों के संबंध में राज्यों की मांग पूरी कर दी है। हालांकि, यदि ऐसी और मांग की जाती है तो हम ये ट्रेनें फिर से परिचालित करेंगे।

वेंकैया का बाल गंगाधर तिलक को नमन

नईदिल्ली। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को उनकी जन्म जयंती पर नमन किया है। नायडू ने गुरुवार को एक ट्वीट में कहा कि बाल गंगाधर तिलक समाज के लिए प्रेरणा थे।उन्होंने कहा, च्राष्ट्र के समक्ष ऐसे उदात्त आदर्शों के प्रणेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जन्म जयंती पर आदर्श पुरुष के यश और उनकी पुण्य स्मृति को सादर प्रणाम करता हूं।

उपराष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में बाल गंगाधर तिलक के एक कथन का भी उल्लेख किया जिसमें उन्होंने समाज सेवा को ही संन्यास बताया है। श्री नायडू ने लिखा-च्धर्म और व्यावहारिक जीवन अलग नहीं हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर नहीं लगेगी रोक

सुको में होगी सोमवार को सुनवाई

नई दिल्ली(आरएनएस)। राजस्थान में सियासी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आ जाए, उसके बाद सोमवार को फिर इस मामले की सुनवाई होगी।आपको बता दे कि स्पीकर डॉ. सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के आदेशों को लेकर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। हाईकोर्ट 24 जुलाई को सचिन पायलट गुट के विधायकों की याचिका पर अपना फैसला सुनायेगा। इससे पहले स्पीकर को अपना फैसला सुनाने को लेकर हाईकोर्ट ने स्पीकर से आग्रह किया था।

पीएम मोदी ने मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी

नईदिल्ली(आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना की लागत 3054.58 करोड़ रुपये है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मणिपुर के करीब 25 लाख गरीब भाई-बहनों को मुफ्त अनाज मिला है। इसी तरह डेढ़ लाख से अधिक बहनों को उज्जवला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर की सुविधा दी गई है।

सुरक्षा, वेतन वृद्धि, हेल्थ इंश्योरेंस छुट्टी जैसे कई सुविधाएं की मांग

एम्स की 400 नर्सों के हड़ताल पर जाने से मरीजों को हो रही परेशानी

पटना (आरएनएस)। कोविड-19 के चलते समूचे देश के साथ बिहार भी बेहाल है। हालत यह है कि मरीजों को बेड तक मिलना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं लोगों के लिए मुसीबत बन रही हैं। इस मुश्किल घड़ी के बीच, पटना स्थित एम्स की 400 संविदा नर्सें हड़ताल पर चली गई हैं, जिससे मरीजों की परेशानी और बढ़ गई है। हड़ताल पर गई नर्सें अपनी नौकरी की सुरक्षा, वेतन वृद्धि, हेल्थ इंश्योरेंस और स्थायी कर्मचारियों की तरह छुट्टी जैसे कई सुविधाएं मांग रही हैं।

बता दें कि पटना एम्स बिहार का इकलौता केंद्रीय हॉस्पिटल है, जहां कई वीवीआईपी कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। ऐसे में हड़ताल से हालत बिगड़ सकते हैं। एम्स प्रशासन कहना है कि हमने कुछ मांगों को मान लिया है। हालांकि अभी भी नर्सों की हड़ताल जारी है। इसका खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है।

गौरतलब है कि बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 30 हजार 369 को पार कर गया है, जिसमें 217 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से अब तक 19 हजार से अधिक मरीज जंग जीत चुके हैं, जबकि 10 हजार से अधिक मरीज अभी भी कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। दो दिन पहले बीजेपी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह की मौत हुई थी और अब बुधवार को आरजेडी नेता राजकिशोर यादव का निधन हो गया है। राजकिशोर दानापुर सीट से आरजेडी के प्रत्याशी रहे हैं और उनकी लालू यादव के करीबी नेता के तौर पर गिनती होती थी।